इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2019—कार्तिक 24, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 3-100-18 अठारह-5.—मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 58 के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था अथवा निकाय से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में,—

(1) उप–नियम (2) में,—

(क) खण्ड (आठ) में, शब्द "वाणिज्यिक प्रयोजन" के स्थान पर, शब्द "वाणिज्यिक, आवासीय–सह–व्यावसायिक एवं मिश्रित भू उपयोग प्रयोजन" स्थापित किए जाएं।

(ख) खण्ड (आठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(नौ) कॉर्नर का भूखण्ड होने की स्थिति में, नियत मूल्य कलक्टर गाईडलाईन के अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सहित होगा।"।

(2) उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(3) किसी योजना के अधीन लॉटरी/आबंटन के माध्यम से विक्रय के लिए शेष ऐसे भवनों/भूखण्डों/वासगृहों, जो कि विज्ञापित किए गए थे, की उपलब्धता की दशा में यदि कोई आबंटिती भवन/भूखण्ड/वासगृह के उक्त आबंटन के क्रमांक का परिवर्तन कराने का इच्छुक है, तो ऐसा प्रीमियम राशि अथवा प्रचलित कलक्टर गाईडलाईन मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, उक्त आबंटिती द्वारा वांछित परिवर्तन के लिए परिवर्तन शुल्क के रूप में जमा किए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा।"।

2.. नियम 11 में, उप–नियम (1) में, शब्द "ऐसी किश्तों पर अधिकतम ब्याज की दर भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा अनुसूचित ऋण दर में दो प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जाएगी" के स्थान पर, शब्द "ऐसी किश्तों की ब्याज 10 प्रतिशत जोड़कर निर्धारित की जाएगी" स्थापित किए जाएं।

3. नियम 15 में,—

(1) उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) पट्टे की नियत अवधि समाप्त होने पर, मूल पट्टा अनुबंध में जिस प्रयोजन हेतु भूमि आबंटित की गई थी उसी प्रयोजन हेतु आगामी तीस वर्षों की अवधि के लिए पट्टे को नवीनीकरण करने की शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होगी, परन्तु नवीनीकरण के दौरान प्रीमियम राशि का निर्धारण आवासीय भू–खण्ड/भवन हेतु प्रचलित बाजार दर का 0.5 प्रतिशत निर्धारित की जाएगी। आवासीय–सह–वाणिज्यिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग होने की दशा में प्रचलित बाजार दर का 1 प्रतिशत तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक प्रयोजन हेतु प्रचलित बाजार दर का 0.25 प्रतिशत एवं पट्टा–भाटक मूल पट्टा भाटक का चार गुना अथवा प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, निर्धारित किया जाएगा :

परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवीनीकरण के मामलों के संबंध में रिपोर्ट संचालक मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।"

(2) उप–नियम (3) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(एक) सम्पत्ति व्ययन के मामलों प्रकरणों में, पट्टे के नवीनीकरण के समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबकि पट्टे के निबंधनों के उल्लंघन एवं उल्लंघन के मामलों में शमन के मामलों में संचालक मण्डल में निहित होंगे ;"।

4. नियम 19 में, उप–नियम (1) में, शब्द तथा अंक "अंतरण शुल्क रू. 5,000/– से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "इस हेतु, अंतरण शुल्क कलक्टर गाईड लाइन के अनुसार 0.25 प्रतिशत अथवा रूपये 5000/– जो भी अधिक हो, देय होगा" स्थापित किए जाएं।

5. नियम 22 में, उप–नियम (1) में, सारणी में,–

(1) अनुक्रमांक (3) के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टियों के अन्त में पूर्ण विराम से पहले, निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"हस्तांतरण शुल्क एवं हस्तांतरण शुल्क पर ब्याज की गणना विक्रय पत्र के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी "।

(2) अनुक्रमांक (4) के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टियों के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और कॉलन के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"परन्तु उपरोक्त उपबंध केवल पट्टा अवधि के दौरान लागू होंगे।"।

6. नियम 32 में,–

(1) उप–नियम (1) में, शब्द "पट्टाधारी" के स्थान पर, शब्द "पट्टाधारी/आबंटिती" स्थापित किए जाएं।

(2) उप–नियम (2) में, शब्द "पट्टाधारी" के स्थान पर, शब्द "पट्टाधारी/आबंटिती" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ–03–100–2018–18–5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक–एफ–3–100–2018–अठारह–5, दिनांक 25 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 25th October 2019

F.No.F-3-100/18/18-5:- The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Vikas Pradhikarano Ki Sampatiyon Ka Prabandhan Tatha Vyayan Niyam, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 85 read with section 58 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken in to

consideration on the expiry of 15 days from the date of their publication of this Notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received with respect to the said draft of amendments from any person, institution or body by the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan Bhopal, on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules-

1. In rule 8,-

(1) In sub-rule (2),-

(a) In clause (viii), for the words, "commercial purpose" the words, "commercial, residential-cum-professional and mixed land use purpose" shall be substituted.

(b) After clause (viii), the following clause shall be added, namely:-

"(ix) In case of corner plot, the fixed price shall be inclusive of 10% additional amount as per the Collector Guideline.".

(2) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:–

"(3) In case of availability of remaining buildings/plots/ tenements for sale through lottery/allotment under a scheme which were put to advertisement, if any allottee is

desirous of any change of serial number of the said allotment of building/ plot/ tenement, the same shall be carried out only after deposit of premium amount or 5% of prevailing Collector Guideline price, whichever is higher, by the said allottee as conversion fee in respect of the desired change.".

2. In rule 11, in sub-rule (1), for the words, "rate of interest on such installments will be fixed by adding two percent on the interest rate scheduled by the Reserve Bank of India", the words, "Rate of interest on such installments shall be fixed by adding 10%" shall be substituted.

3. In rule 15,-

(1) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Upon expiry of fixed period of lease, the power to renew the lease for a period of thirty years for the same use for which the land was allotted in the original lease deed shall be vested in the chief Executive Officer, but during renewal, the premium amount will be determined on 0.5% of prevailing market rate for residential plots/ building. In case of use of land for residential - cum - commercial, commercial and industrial purpose 1% of prevailing market rate and for public and semi public purpose 0.25% of prevailing market rate and lease rent shall be determined on four times of the original

lease rent or 0.5% of the prevailing market value, whichever is less :

Provided that the Chief Executive Officer shall submit report in respect of the renewal cases in the next meeting of the Board of Directors."

(2) In sub-rule (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) In property disposal cases, the right towards renewal of the lease shall vest with the Chief Executive officer whereas renewal of lease in cases of violation of terms of lease and compounding in matter of violation shall vest with the Board of Directors;".

4. In rule 19, in sub-rule (1), for the words and figure, "The transfer fee shall not be more than Rs 5000/-", the words and figure, "Towards this, the transfer fee of 0.25%as per collector guide line or Rs 5000/- whichever is higher shall be payable." shall be substituted.

5. In rule 22, in sub-rule (1), in the table,-

(1) Against serial No (3), in column (2) in the end of entries before full stop, the following words shall be inserted, namely:-

"the calculation of transfer fee and interest on transfer fee shall be carried out from the date of registration of the sale deed".

(2) Against serial No (4), in column (3) in the end of entries, for full stop, colon shall be substituted and after colon the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the above provisions shall apply during lease period only.".

6. In rule 32,-

(1) In sub-rule (1), for the words "lease holder", the words "lease holder/allottee" shall be substituted.

(2) In sub-rule (2), for the words "lease holder", the words "lease holder/allottee" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

Bhopal, the 14th November 2019

No. 1574 /MPERC/2019 - In exercise of power conferred under section 181(2) (zd) read with Section 45 and section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) ,the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, [2015(RG-35(II) of 2015]" .

Whereas, the Commission had notified Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of tariff for Supply and wheeling of Electricity and Methods & Principles for Fixation of Charges) Regulations, (First Amendment) Regulations, [2015(RG-35(II)(i) of 2015 on 7th December 2018 and whereas the third control period of Multi Year Tariff will cease to be in vogue on 31st March, 2020. In order to specify the terms and conditions for Distribution Tariff for the next Financial Year 2020-21, these Regulations are being amended.

Short title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, (Second Amendment) Regulations, 2015"

(ii) These Regulations shall come in force with effect from 01.04.2020, and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of one year, i.e., up to 31.03.2021. Except for the following amendments, all other provisions and term & conditions of principal Regulations shall remain unchanged.

(iii)These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

Amendment to Regulations 1.3, 8.1 , 8.4 , 16, 17.1, 25.1, 31.3, 34.6 (b) (i) and (ii)

In Principal Regulations, under Regulations 1.3, 8.1, 16 and 25.1 the word " 31st March 2020" shall be substituted by the word "31st March 2021".

In Principal Regulations, under Regulations 8.4, the word "31st October every year" shall be substituted by "30st November for FY2020-21".

In principal Regulations, under Regulations 17.1, the word "three years" shall be substituted by the word "five years".

In Principal Regulations, under Regulations 25.1, the normative distribution loss level trajectory for control period of these Regulations shall be substituted as per table below

Sr. No.	Distribution Licensee	FY16-17	FY17-18	FY18-19	FY19-20	FY20-21
1	East Discom	18%	17%	16%	16%	16%
2	West Discom	16%	15.5%	15%	15%	15%
3	Central Discom	19%	18%	17%	17%	17%
4	SEZ ,Pithampur	2.0%	1.9%	1.8%	1.8%	1.5%

In Principal Regulations, under Regulations 31.3 , the year "2018-19" shall be substituted by year "2020-21"

In Principal Regulations, the Regulations 34.6 (b) (i) & (ii) shall be substituted as under:

(i) Employee expenses excluding dearness allowance, NPS expenses, pension, terminal benefits and incentive to be paid to employees :

(Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	385	403	359	0.98
2017-18	396	415	370	1.01
2018-19	408	428	381	1.04
2019-20	1080	1133	1009	2.75
2020-21	1080	1133	1009	2.75

ii) A& G expenses (Rs. in Crore)

FY	East Discom	West Discom	Central Discom	SEZ Pithampur
2016-17	168	129	96	1.91
2017-18	179	138	103	2.04
2018-19	192	147	110	2.18
2019-20	205	157	118	2.33
2020-21	205	157	118	2.33

The information required in the formats annexed with the Principal Regulations shall be applicable for FY2020-21 also .

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.